

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/आषाढ़ 24, 1936 No. 203] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

# महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुंबई, 11 जुलाई, 2014

सं.टीएएमपी/73/2012-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, कांडला पत्तन न्यास द्वारा अपने प्रचलित दरमान के संशोधन हेतु दाखिल किये गये प्रस्ताव को, संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

# महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण प्रकण सं. टीएएमपी/73/2012-केपीटी गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चंद्रभान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

#### आदेश

### (जुलाई 2014 के 4थे दिन पारित)

यह आदेश कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा अपने प्रचलित दरमान (एसओआर) के संशोधन हेतु दाखिल किये गये प्रस्ताव से संबंधित है।

2. केपीटी का प्रचलित दरमान, इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार, आदेश सं.टीएएमपी/61/2009-केपीटी, दिनांक 18 जनवरी 2011 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था जो भारत का राजपत्र में 22 फरवरी 2011 को अधिसूचित किया गया था। दिनांक 18 जनवरी 2001 के आदेश ने, दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 तक प्रदान की है।

2881 GI/2014 (1)

- 3.1. केपीटी ने अपने दरमान के संशोधन हेतु 16 जनवरी 2013 को अपना प्रस्ताव दाखिल किया है जिसका पंजीकरण एक प्रशुल्क प्रकरण रूप में किया गया है और इसे संबंधित स्टेकधारकों से परामर्श के लिए लिया गया है। प्रस्ताव की प्रारंभिक छानबीन के बाद अतिरिक्त जानकारी / स्पष्टीकरण मांगते हुए 17 अप्रैल 2013 को पत्तन को एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई है। केपीटी ने, दिनांक 7 अगस्त 2013 के अपने पत्र के जिरए, प्रस्तुत किया है कि वह वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखा के आधार पर लागत विवरणी अद्यनित कर रहा है और व्यापार जगत की सहमित और अपने न्यासी मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कुछ और समय लग सकता है।
- 3.2. बाद में, केपीटी ने, दिनांक 26 नवंबर 2013 के पत्र के जिरए, अन्य बातों के अलावा, बताया है कि पत्तन ने अपना प्रस्ताव, 2012-13 के वित्त परिणाम अद्यनित करते हुए, दोबारा तैयार किया है और परामर्श हेतु उपयोक्ताओं को परिपत्रित किया है। अपने बोर्ड का अनुमोदन मांगने के बाद, केपीटी ने, अपने बोर्ड की आगामी बैठक में (इसका) अनुमोदन मांग कर, अपने संशोधित प्रस्ताव को दाखिल करने के लिए सहमित व्यक्त की है। इसके कारण पत्तन ने यह प्रकरण बंद नहीं करने का अनुरोध किया है।
- 3.3. केपीटी के अनुरोध पर विचार करते हुए, इस प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि केपीटी को अपना प्रस्ताव दाखिल करने हेतु 15 फरवरी 2014 तक का समय दिया जाए और साथ ही पत्तन को यह पुष्टि करने हेतु सलाह भी दी थी कि (दाखिल किया जाने) वाला संशोधित प्रस्ताव, दिनांक 26 नवंबर 2013 के केपीटी के पत्र द्वारा अग्रेषित, संसद-सदस्यों की सलाहकार समिति की दिनांक 15 अप्रैल 2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज सचिव (पोत परिवहन) के निदेशों के अनुरूप संयुक्त सचिव (पत्तन) के परामर्श के अनुसार है।
- 3.4. अब केपीटी ने, दिनांक 16 मई 2014 के अपने पत्र के जिरए, 24 मार्च 2014 को आयोजित अपने न्यासी मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करते हुए, इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह इसके दरमान के संशोधन-प्रस्ताव को आस्थिगित रखे। साथ ही इसने अनुरोध किया है कि इसके प्रचलित दरमान की वैधता को विस्तारित किया जाए।
- 3.5. केपीटी द्वारा इसके प्रचलित दरमान की वैधता विस्तारित करने हेतु किए गए अनुरोध के संदर्भ में, इस प्राधिकरण ने सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी दिनांक 4 जुलाई 2014 को एक पृथक आदेश पारित किया है।
- 4.1. केपीटी द्वारा इसके दरमान के संशोधन प्रस्ताव को आस्थिगित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्राधिकरण को समय-समय पर महापत्तन न्यासों द्वारा प्रदत्त कार्गों और पोत संबंधी, दोनों सेवाओं के लिए वहां प्रचलित महापत्तन न्यासों और निजी टर्मिनलों का प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के तहत आदेश प्राप्त है। 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 3.1.8 के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रशुल्क की प्रत्येक तीन वर्ष में समीक्षा की जानी है। प्रचलित दरमान के संशोधन हेतु केपीटी द्वारा दाखिल किये गए दिनांक 3 जनवरी 2013 के प्रस्ताव पर सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्रवाई की गई थी और पत्तन से अतिरिक्त जानकारी / स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। तथापि, केपीटी ने निरंतर याद दिलाने के बावजूद मांगी गई प्रासंगिक जानकारी / स्पष्टीकरण अब तक प्रस्तुत नहीं किया है। इतना ही नहीं, संदर्भित प्रस्ताव हेतु जून 2013 में आयोजित संयुक्त सुनवाई भी केपीटी के अनुरोध पर रद्द की गई थी।
- 4.2. केपीटी ने दिनांक 17 अप्रैल 2013 के हमारे पत्र के माध्यम से मांगी गई अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही पत्तन ने अपने दरमान के संशोधन हेतु संशोधित / अद्यतन प्रस्ताव दाखिल किया है। केपीटी द्वारा अपने दरमान के संशोधन हेतु दाखिल किए गए वर्तमान प्रस्ताव को जनवरी 2013 में एक प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया था जो डेढ़ वर्ष से अधिक समय से लंबित है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इसके पहले भी इस प्राधिकरण ने केपीटी द्वारा इसके प्रकरण को बंद नहीं करने के लिए किए गए अनुरोध को मान लिया था। केपीटी को अपना प्रस्ताव दाखिल करने हेतु 15 फरवरी 2014 तक समय दिया गया था। किंतु, केपीटी ने अपना संशोधित प्रस्ताव अब तक दाखिल नहीं किया है। इस बार केपीटी ने, अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा सूचित किए बिना ही, इसके प्रस्ताव को आस्थिगत रखने हेतु अनुरोध किया है। चूंकि, प्राप्त प्रस्ताव को एक "प्रशुल्क प्रकरण" के रूप में प्राप्त किया गया है, प्रस्ताव को

अनिश्चित समय के लिए लंबित रखना उचित नहीं होगा। किसी भी हालत में, केपीटी द्वारा प्रस्तुत (किया जाने वाला) प्रस्ताव 2013-14 के वास्तविकों पर आधारित होना चाहिए और इस कारण सभी सम्बद्ध स्टेकधारकों से एक बार और परामर्श लेना आवश्यक होगा और प्रस्ताव की छानबीन ताजा रूप से करना भी आवश्यक होगा। इसलिए, केपीटी से संशोधित प्रस्ताव की अपेक्षा करते हुए, यही उचित समझा गया है कि (इस) प्रकरण को बंद कर दिया जाए। ताजा प्रस्ताव जब प्राप्त होगा (तब) उसे एक नवीन प्रस्ताव मान लिया जाएगा। केपीटी ने अपना अद्यतन संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की है। चूंकि केपीटी के दरमान के संशोधन पहले से ही विलंबित है और केपीटी द्वारा ताजातरीन प्रस्ताव भी दाखिल करना अब तक बाकी है, यह प्राधिकरण, एतद्द्वारा, केपीटी को सलाह देता है कि अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु 2013-14 वास्तविकों पर आधारित अपना ताजातरीन प्रस्ताव अधिकतम 31 अगस्त 2014 तक दाखिल कर दे, जो (प्रस्ताव) नवीन माना जाएगा।

- 5.1. ऊपर दिये गए कारणों से, यह प्राधिकरण, केपीटी द्वारा अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु दाखिल किये गये प्रस्ताव को जो प्रकरण सं. टीएएमपी/73/2012-केपीटी दिनांक 16 जनवरी 2013 के रूप में पंजीकृत किया गया था, केपीटी से संशोधित प्रस्ताव की अपेक्षा करते हुए बंद करने का निर्णय करता है। केपीटी से प्राप्त होने वाले नवीन प्रस्ताव को, प्राप्त होने के बाद नया माना जाएगा।
- 5.2. केपीटी को निदेश दिया जाता है कि 2013-14 वास्तविकों के आधार अपना नया प्रस्ताव अधिकतम 31 अगस्त 2014 तक अवश्य दाखिल कर दें।

टी.एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/2014]

# TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 11th July, 2014

**No. TAMP/73/2012-KPT.**—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal filed by the Kandla Port Trust for revision of its existing Scale of Rates as in the Order appended hereto.

# TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No.TAMP/73/2012-KPT OUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

#### **ORDER**

(Passed on 4th day of July, 2014)

This Order relates to the proposal filed by the Kandla Port Trust (KPT) for revision of its existing Scale of Rates (SOR).

- 2. The existing Scale of Rates (SOR) of the KPT was last approved by this Authority vide Order No.TAMP/61/2009-KPT dated 18 January 2011 which was notified in the Gazette of India on 22 February 2011. The Order dated 18 January 2011 prescribed validity of the SOR till 31 March 2013.
- 3.1. The KPT has filed its proposal for revision of its SOR which is registered as tariff case on 16 January 2013 and is taken on consultation with the relevant stakeholders. On preliminary scrutiny of the proposal a detailed questionnaire is issued to the port on 17 April 2013 seeking additional information/clarification. The KPT, vide its letter dated 7 August 2013, submitted that it is updating the cost statements based on Annual Accounts for the year 2012-13 and it will take time for obtaining consent of the trade and approval of its Board.

- 3.2. Subsequently, the KPT, vide its letter dated 26 November 2013, *inter alia*, stated that the port has reformulated its proposal updating financial results of 2012-13 and circulated it to users for consultation. After seeking approval of its Board, the KPT had agreed to submit its revised proposal after seeking approval of its Board in the ensuing meeting. In view of that the port had requested not to close the case.
- 3.3. Considering the request of the KPT, this Authority decided to grant time till 15 February 2014 to KPT to file its proposal and had also advised the port to confirm that the revised proposal (to be) filed is in consultation with the Joint Secretary (Ports) as per direction of the Secretary (Shipping) recorded in the Minutes of the Meeting dated 15 April 2013 of the Consultative Committee of the Members of the Parliament forwarded by KPT vide its letter dated 26 November 2013.
- 3.4. The KPT now, vide its letter dated 16 May 2014, while attaching the minutes of the meeting of its Board of Trustees held on 24 March 2014, has requested this Authority to keep in abeyance its proposal for revision of its SOR. It has also simultaneously requested to extend the validity of its existing SOR.
- 3.5. With reference to the request of the KPT for extending the validity of its existing SOR, this Authority has passed a separate Order No.TAMP/61/2009-KPT dated 04 July 2014.
- 4.1. With reference to the request of the KPT to keep in abeyance its proposal for revision of its SOR, it is noteworthy that this Authority is mandated under the Major Port Trusts Act, 1963 to determine tariff of Major Port Trusts and Private Terminals operating thereat for both cargo and vessel related services provided by the Major Port Trusts from time to time. As per clause 3.1.8. of the 2005 tariff guidelines, tariff fixed by this Authority is to be reviewed every three years. The proposal dated 3 January 2013 filed by the KPT for revision of the existing SOR was processed following the usual consultation process and additional information/clarification was also sought from the port. The KPT has, however, not furnished the relevant information/clarification sought so far despite reminders. Even the joint hearing set up on the subject proposal in June 2013 was cancelled at the request of the KPT.
- 4.2. The KPT has not furnished additional information /clarification sought vide our letter dated 17 April 2013 nor has the port filed revised / updated proposal for revision of its SOR. The existing proposal filed by KPT for revision of its SOR is registered as a tariff case in January 2013 and is pending for more than one and half year. It is relevant to state here on the earlier occasion as well, this Authority had acceded to the request made by the KPT not to close its case. The KPT was granted time till 15 February 2014 to file its proposal. But, the KPT has not yet filed its revised proposal. The KPT has now requested to keep its proposal in abeyance without indicating any specific time frame to file its proposal. Since the proposal is received as a "tariff case", it will not be appropriate to keep the proposal pending indefinitely. In any case, the revised proposal (to be) filed by the KPT will have to be based on 2013-14 actuals and this will require fresh consultation with all the concerned stakeholders and will also require fresh scrutiny of proposal. Hence, it is found appropriate to close the case for want of revised proposal from KPT. Fresh proposal when received shall be treated afresh. The KPT has not specified any time frame for filing its revised updated proposal. Since the SOR of KPT is already overdue for revision and fresh proposal is yet to be filed by KPT, this Authority hereby advises the KPT to file its fresh proposal for general revision of its SOR based on 2013-14 actuals latest by 31 August 2014 which will be treated afresh.
- 5.1. In view of the reasons given above this Authority decides to close the proposal of the KPT for general revision of its Scale of Rates registered as case No. TAMP/73/2012-KPT on 16 January 2013 for want of revised proposal from the KPT. The fresh proposal when received from the KPT shall be treated afresh.
- 5.2. The KPT is directed to file its fresh proposal based on 2013-14 actuals latest by 31 August 2014.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2014]